सं ग्रो.वि./एफ.डो./206-84/48070.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. ए.एस.बी. रवड़ इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., 22-ए, एनक्प्राई.टी., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम ग्रवध तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है :

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायानण्य हेत् निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1.947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुन हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अविस्चना सं. 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायिनर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से ससंगत प्रथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री राम अवध की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का . हकदार है ?

सं० स्रो० वि०/एफ. डी./83-85/48077.—चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० रजत इन्डस्ट्रीज, प्लाट नं. 151,, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मग्गन लाल तथा उसके प्रन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई • सौद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, श्रव, श्रोद्योगिक विवाद श्रवितियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा कारी श्रिधसूचना सं० 5415—3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए श्रविसूचना सं० 11495—जी श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उबत श्रिधिनियम की धारा 7 के श्रवीन गठित श्रम न्यायालय, फरोदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिश्य करते हैं जो कि कित प्रवन्त की तथा श्रीमक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री मग्गन लाल की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किह राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो.वि/एफ.डी./29-85/48084.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. एलकोजिन इण्डिया प्रा० लि०, प्लाट नं० 16, सैक्टर 4, बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री एस०एस० नागर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, श्रव, श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रवान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून 1968, के साथ पढ़ते हुए श्रधिसूचना सं. 11495-जो-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त श्रधिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित वम न्यायालय फरीदावाद, को विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निद्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रवन्धों तथा श्रमिक के बीव या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रथवा संबंधित मामला है :—

बया श्री एस०एस० नागर की सेवाशों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो. ति./एफ.डी./187-85/48091. --चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. जैको स्टील फस्टनर्स प्रा०
लि०, 269/24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री विनोद कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई
ग्रीखोंगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए. अब, भौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई अक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-अस-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 जी-अम-57/112445, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अवोग गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करने हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अभिक के अधि या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधवा सम्बन्धित मामला हैं:--

वया श्री विनोद कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?